

[श्री हरीश रावत]

6. स्थान पिथौरागढ़, जोकि इस यात्रा मार्ग का महत्वपूर्ण केन्द्र स्थान है यहां एक हवाई अड्डे का निर्माण करने तथा इसे वायुदूत सेवाओं से शीघ्र सम्बद्ध किए जाने हेतु नागरिक उड्डयन विभाग से वार्ता की जानी चाहिए।

7. इस यात्रा मार्ग के धारचूल मुन्सियारी क्षेत्रों के निवासियों को जिन्हें तिब्बत के क्षेत्र का व्यापक अनुभव है उन्हें टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग देकर इन यात्रा ट्रप्स के मार्गदर्शन का दायित्व सौंपा जाना चाहिए।

8. इस यात्रा को सामान्य व्यक्ति के लिए सुलभ बनाने हेतु सामान्य यात्रा गाड़ियों तथा जनता भोजनालयों की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

9. तिब्बत क्षेत्र में यात्रा के संयोजन हेतु तकलाकोट में कंसुलेट कार्यालय खोले जाने हेतु चीन सरकार से वार्ता की जानी चाहिए।

10 चीन क्षेत्र में यात्रा को अधिक सुगम व उपयुक्त बनाने हेतु ताकि यात्रियों को सामान्य भारतीय भोजन आदि प्राप्त हो सके इस सन्दर्भ में चीन सरकार से वार्ता की जानी चाहिए।

11. निषिद्ध क्षेत्र, जौलजीवी के बजाए गुन्जी से आगे के क्षेत्र को घोषित किया जाना चाहिए।

12. अधिक उपयुक्त होगा इस यात्रा की व्यवस्था एवं संचालन आदि हेतु एक समिति जिनमें जनप्रतिनिधि यात्रा लाइन क्षेत्र के प्रतिनिधि, सरकारी प्रतिनिधि आदि सम्मिलित हों, बनाई जानी चाहिए।

13. स्वामी परमानन्द जी जिन्हें इन पुण्य स्थानों की यात्रा का व्यापक अनुभव है तथा जिन्होंने इस सन्दर्भ में पुस्तक

लिखी उस पुस्तक को सरकार को चाहिए कि अधिक मात्रा में छपवाने की व्यवस्था करे ताकि यात्री इस पुस्तक के माध्यम से यात्रा का पूर्वानुमान कर सकें।

अतः विदेश मंत्री जी से अनुरोध है कि उपरोक्त क्रम में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करें।

13.00 hrsfl

(ii) FINANCIAL ASSISTANCE TO HIMACHAL PRADESH FOR RELIEF MEASURES IN AREA AFFECTED BY HAILSTONE AND HEAVY RAINS.

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी (शिमला) : हाल ही में हिमाचल में भीषण ओलावृष्टि तथा हिमपात हुए हैं, जिनके कारण काफी नुक्सान हुआ है। खड़ी फसलें नष्ट हुई हैं तथा मकानों, सड़कों आदि को भी भारी हानि पहुंची है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार अति शीत आदि के कारण कई व्यक्तियों की भी मृत्यु हुई है। हिमपात के कारण सारी यातायात एवं संचार की व्यवस्था ठप्प हो गई है, जिसके कारण वहां की जनता को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः इस महत्वपूर्ण समस्या को लोक सभा में उठाकर सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित कराया जाना उचित है।

इसके अलावा जिला सिरमौर में वता नदी गिरि जमुना, लालागढ़ में सरका नदी तथा छोटी-छोटी नदियों में बहुत ज्यादा पानी आने के कारण बहुत से लोगों की जमीन इससे खराब हो गई है। जिला शिमला में सेब के वृक्ष नष्ट हो चुके हैं। सरकारी जंगलों में जो वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण हुआ था वह भी नष्ट हो गए हैं। जिन भूमिहीन लोगों को 20 सूत्री प्रोग्राम में भूमि दी गई थी उनकी भूमि भी उससे नष्ट हो गई है, जिसकी पूर्ति

कराना राज्य सरकार के बस की बात नहीं रही है। मैं भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय से जोरदार मांग करूंगा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को आर्थिक रूप से ज्यादा से ज्यादा सहायता प्रदान की जाए ताकि राज्य सरकार जो यह नष्ट हुई फसलों, वृक्ष और गरीब लोगों की भूमि, मकान, सड़कें इत्यादि जो भी खराब हुई हैं, उनकी पूर्ति कर सके।

(iii) ALLEGED EXPLOITATION OF LABOURERS ENGAGED IN STONE QUARIES AND CRUSHERS BY CONTRACTORS

श्री बोलत राम सारण (चुरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन खान मजदूर भयंकर शोषण के शिकार के सम्बन्ध में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ :

मेवला महाराजपुर जिसे गधा-खोर भी कहते हैं, गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ लकड़पुर, अनंगपुर, सराय कटन क्षेत्र की पत्थर की खानों और वहां लगे क्रेशरों पर दस हजार से भी अधिक खान मजदूर काम करते हैं। इन खान मजदूरों का ठकेदार बुरी तरह से शोषण कर रहे हैं।

ये खान मजदूर मद्रास, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और ठकेदारों द्वारा हरियाणा के हैं। इन हजारों मजदूरों को ठकेदार द्वारा कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता। इनमें से अधिकांश स्थानीय भाषा हिन्दी नहीं समझते। इन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती। आवास, चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा, शुद्ध पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। बरसात का इकट्ठा हुआ गन्दा पानी पीते हैं, जिससे गैंग्वा में मलेरिया आदि से बीमार हैं। इन्हें सस्ते भाव पर अनाज आदि जीवनोपयोगी वस्तुएं देने की भी कोई व्यवस्था नहीं है।

अन्तर्राज्यीय विस्थापित मजदूर अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि श्रमिकों के लाभ और उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए किसी कानून के अन्तर्गत इन्हें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और न ही कोई व्यवस्था है। इन हजारों मजदूरों का भयंकर शोषण और उत्पीड़न हो रहा है। ये मजदूर केवल ठकेदारों के रहम पर जी रहे हैं।

इन हजारों मजदूरों की चिन्ताजनक स्थिति से इनकी रक्षा की जाए। इनका शोषण उत्पीड़न समाप्त किया जाए। ये खानें, मजदूरों को सहकारी समितियां बना कर उन्हें पट्टे पर दी जायें, उन्हें ही क्रेशर लगवा कर दिए जायें और ठकेदारी प्रथा समाप्त करके इनका शोषण समाप्त किया जाए।

आशा है सरकार का श्रम विभाग इस ओर ध्यान दे कर इन्हें राहत दिलाएगा।

(iv) ESTABLISHMENTS OF TWO MORE ATOMIC POWER UNITS TO SOLVE POWER CRISES IN RAJASTHAN

प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : भारत में बिजली का संकट और अधिक बढ़ता जा रहा है इस से कृषि तथा लघु उद्योग बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। राजस्थान की स्थिति और भी अधिक दयनीय है। राष्ट्र के गौरव का प्रतीक राजस्थान परमाणु बिजली घर 8 वर्ष से लगातार बीमार चल रहे हैं। वर्तमान में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के बीच चार बिजली परियोजनाओं में साझेदारी है। गांधी सागर और सतमुडा से मध्य प्रदेश राजस्थान को बिजली नहीं दे रहा है। इधर रावतमाटा परमाणु बिजली घर का यह रिकार्ड है कि नियमित रूप से 8 दिन भी लगातार यह नहीं चला। बार-बार इसके बन्द होने से कृषि तथा उद्योगों को भारी क्षति हुई है।

हमें स्वदेशी ईंधन तथा भारी पानी का उपयोग इस में हो सके ऐसी व्यवस्था